https://swadeshbhartnews

R.N.I. No. UPHIN/2021/82888

स्वदेश भारत न्यूज

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

जौनपुर से प्रकाशित

जौनपुर
मंगलवार 19 मई 2026
वर्ष : 05 – अंक : 20
पृष्ठ – 4 मूल्य – 5:00 रूपये

पंचायत आरक्षण आयोग, 1010 बेड अस्पताल समेत 12 प्रस्ताव पास

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी सबसे चर्चित फैसला रहा। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के एमओयू को हरी झंडी मिली, जबकि पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाकर 12000 हजार प्रतिमाह कर दिया गया। कैबिनेट के फैसलों को आगामी चुनावों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव और वेटनरी छात्रों से जुड़े दो बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग का कार्यकाल छह महीने निर्धारित किया गया है। सरकार के अनुसार, आयोग पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2026 तक सामने आ सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार को आयोग गठन का निर्देश दिया था।

वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा

कैबिनेट बैठक में पशु चिकित्सा के छात्रों को भी बड़ी राहत दी गई। बीवीएससी एंड एएच (बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री) के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।प्रदेश के विभिन्न वेटनरी कॉलेजों में हर साल करीब 2 हजार से 2,500 छात्र प्रवेश लेते हैं। वर्तमान में यूपी में 10 हजार से अधिक वेटनरी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

प्रयाराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का विस्तार के लिए जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के मरीजों को फायदा मिलेगा।

मिर्जापुर में बड़ा बिजली उपकेंद्र और नई बिजली लाइनें बनेंगी। इस पर करीब 2800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों को बेहतर और लगातार बिजली मिलेगी। उद्योगों को फायदा होगा और निवेश बढ़ेगा।

लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जाएगा। इस पर करीब 855 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो कॉरिडोर-2 में आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

बस्तर में शाह का विकास मॉडलः केंद्रीय गृह मंत्री बोले- नक्सलवाद खत्म अब रोजगार के नए अवसर

बस्तर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे और क्षेत्र के तीव्र विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी नक्सलवाद के समाप्त होने के बावजूद शांति से न बैठने का आग्रह किया है। शाह ने बताया कि नक्सलवाद का वास्तविक उन्मूलन तभी होगा जब अगले 5 साल में हुई क्षति की पूरी भरपाई कर दी जाएगी।गृह मंत्री ने कहा कि सभी गांवों को जीवंत आदिवासी समुदायों में बदला जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डेयरी क्षेत्र और वनोपज मिलकर रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। शाह ने कहा देश को 77-78 साल पहले आजादी मिली, लेकिन बस्तर के लिए सच्ची आजादी 31 मार्च, 2026 के बाद ही आएगी।उन्होंने यह भी कहा कि इस देरी से हुए नुकसान की भरपाई तेजी से की जाएगी। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। शाह ने नक्सलवादियों के इस गलत प्रचार को खारिज किया कि उन्होंने विकास न होने के कारण हथियार उठाए थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नक्सलवादी हथियारों के साथ वहां बैठे थे। उनके आत्मसमर्पण से अब विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है।शाह ने घोषणा की कि एक साल के भीतर सरकार सीधे गांवों तक पहुंचेगी। अब किसी को भी रायपुर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बस्तर में वर्तमान में 196 शिविर हैं, कुल मिलाकर लगभग 200 शिविर हैं। अगले 1.5 साल में इनमें से 70 शिविरों को 'सेवा गांव' में बदला जाएगा। इन 'सेवा गांव' को आदिवासी कल्याण के लिए समर्पित केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा। शाह ने कहा कि वह कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को इसकी घोषणा करेंगे। यह पहल आदिवासी समुदायों के उत्थान और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

'सिर्फ सरकार-भगवान के भरोसे रहने से नहीं बदलेगा देश', गडकरी ने लोगों से की जनभागीदारी की अपील

नागपुर। नागपुर में आयोजित 'जल संवाद' सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण की रक्षा और देश की तरक्की के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर काम के लिए सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। गडकरी ने समाज की एक बड़ी कमजोरी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि लोग सरकार और भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उनके अनुसार, अगर इन दोनों ने सही ढंग से काम किया होता, तो देश की स्थिति बहुत पहले ही बदल गई होती। गडकरी ने कहा कि देश को बदलने के लिए हमें हर व्यक्ति और समाज को जगाना होगा। जब लोग मिलकर काम करेंगे, तभी बदलाव आएगा। यह सम्मेलन 'पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था' के 25 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया था। यह संस्था महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए काम कर रही है। इस कार्यक्रम में देश भर के जल संरक्षण विशेषज्ञ और कार्यकर्ता शामिल हुए।गडकरी ने संस्था के कामों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि विदर्भ के कई गांवों में इस संस्था के काम का बहुत अच्छा असर हुआ है। वहां सिंचाई की सुविधा बढ़ी है और पुराने कुओं

को फिर से जीवित किया गया है। इससे जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ा है और किसानों ने सोलर पंप लगाए हैं। इन प्रयासों से किसानों का जीवन बेहतर हुआ है। वे कर्ज से मुक्त होने लगे हैं और किसानों की आत्महत्या के मामलों में भी कमी आई है।पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण पर बात करते हुए गडकरी ने नए और परखे हुए मॉडलों को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें सरकार के भरोसे बैठे बिना खुद नए तरीके खोजने होंगे। गडकरी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। इसलिए हमें तकनीक का सहारा लेना होगा।सामाजिक पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, तकनीक, कौशल और सफल प्रयोगों का मेल ही 'ज्ञान' है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस ज्ञान को धन में बदलना ही भविष्य है। उन्होंने सामाजिक प्रयासों से आत्मनिर्भर बनने की बात कही। गडकरी ने अंत में कहा कि संस्था के 25 वर्षों के सफर ने यह साबित कर दिया है कि जनभागीदारी से सब कुछ मुमकिन है।

ओडिशा में भाजपा का मेगा प्लान: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अहम दौरा, बड़ी बैठकों की पूरी रणनीति तैयार

भुवनेश्वर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद नितिन नवीन पहली बार ओडिशा के दौरे पर आए हैं। रविवार को वो भुवनेश्वर पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, कई कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ओडिशा जैसे राज्य में, जहां भाजपा की अपनी सरकार है, वहां पार्टी के सबसे बड़े नेता का आना बहुत ही अहम माना जा रहा है। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यह उनके अध्यक्ष बनने के बाद इस राज्य की पहली यात्रा है। इस दौरे का सीधा सा मतलब है पार्टी की नींव को और ज्यादा मजबूत करना। ओडिशा भाजपा की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि नितिन नवीन सोमवार को भुवनेश्वर और पुरी में कई बड़ी और अहम बैठकें करेंगे। इसके अलावा वह एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। इन सब चीजों का मुख्य मकसद उन छोटे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और जोश भरना है जो एकदम जमीन पर रहकर पार्टी के लिए काम करते हैं।

इसके साथ ही, वह राज्य में चल रहे पार्टी के सभी कामों की जांच-परख करेंगे और आने वाले समय में पार्टी को कैसे और आगे ले जाना है, इसकी एक नई रूपरेखा भी तैयार करेंगे।

सोमवार सुबह भुवनेश्वर में होने वाली बैठकों की क्या है तैयारी?

अगर सोमवार के कार्यक्रमों की बात करें, तो भाजपा अध्यक्ष के दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी और अहम बैठकों के साथ होगी। नितिन नवीन सोमवार की सुबह 8:30 बजे राज्य कोर कमेटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। कोर कमेटी में पार्टी के सबसे खास और बड़े नेता शामिल होते हैं। इस बड़ी बैठक के ठीक दो घंटे बाद, वह भाजपा के भुवनेश्वर जिला प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। यह शिविर इसलिए लगाया जाता है ताकि पार्टी के लोगों को काम करने का सही तरीका सिखाया जा सके और संगठन की ताकत को निचले स्तर तक बढ़ाया जा सके।

पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन और महाप्रसाद का क्या है कार्यक्रम?

लगातार बैठकों और कार्यक्रमों के बाद, दोपहर 1:15 बजे नितिन नवीन भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पुरी शहर जाएंगे। पुरी पूरे देश में भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर के लिए जाना जाता है। वहां जाकर वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे और उनका खास आशीर्वाद मांगेंगे। मंदिर में पूजा करने के बाद, वह पुरी से लोकसभा सांसद और भाजपा के जाने-माने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के घर जाएंगे। संबित पात्रा के आवास पर ही नितिन नवीन भगवान का पवित्र 'महाप्रसाद' ग्रहण करेंगे। यह एक बहुत ही सम्मानजनक और धार्मिक महत्व का पल है। पुरी में भगवान का दर्शन और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद, नितिन नवीन वापस भुवनेश्वर लौट आएंगे। भुवनेश्वर लौटकर शाम 4 बजे वह फिर से काम में जुट जाएंगे। इस समय वह राज्य के पदाधिकारियों और पार्टी के अलग-अलग मोर्चों के अध्यक्षों से सीधी मुलाकात करेंगे और संगठन के कामकाज को समझेंगे। इसके ठीक दो घंटे बाद, यानी शाम 6 बजे उनका एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम है।

'सोशल मीडिया पर लोगों को लुभाकर बन गए सीएम': स्टालिन का विजय पर तीखा हमला, बोले- हम समझ नहीं पाए

चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीमके प्रमुख एम के स्टालिन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ टीवीके ने कोई जमीनी काम नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित कर विधानसभा चुनाव जीत लिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने डीएमवेक की विभिन्न गतिविधियों का जिक्र किया। उन्होंने पार्टी सम्मेलनों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कामों का भी उल्लेख किया। सत्तारूढ़ टीवीके का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि डीएमके की तरह पार्टी ने कोई जमीनी तैयारी नहीं की। यहां तक कि कई जगहों पर उसने मतगणना एजेंट तक नियुक्त नहीं किए थे। स्टालिन ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के जरिए परिवारों को प्रभावित करने के लिए किया गया और यह हमारी नजरों से बच गया। उन्होंने कहा कि डीएमके अब इस बात को समझ चुकी है और आगे से बेहद सतर्क रहेगी। सोशल मीडिया आधारित ऐसी रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए पार्टी ने नई योजनाएं तैयार की गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 1949 में स्थापित डीएमके ने कई चुनावी जीत और हार देखी हैं, लेकिन पार्टी हमेशा की तरह फिर से मजबूती से खड़ी हुई है।तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की जीत ने सभी को चौंकाया है। खुद टीवीके की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्ति चिदंबरम कह चुके हैं कि हमने थलापित विजय को कम करके आंका। स्टालिन ने कहा कि विजय की पार्टी टीवीके का प्रचार काफी मजबूत था और उनकी पार्टी इस ओर ध्यान नहीं दे पायी। हाल ही में सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत ने एमके स्टालिन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की खूब चर्चा हुई। कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि वे नहीं चाहते थे कि विजय मुख्यमंत्री बनें। इसे लेकर रजनीकांत ने रविवार को मीडिया से बातचीत में साफ किया कि वे विजय से नहीं जलते हैं। उन्होंने कहा कि विजय उनसे 25 साल जूनियर हैं। रजनीकांत ने ये भी कहा कि अगर वे 2021 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ते तो जीत जाते।

वियतनाम और दक्षिण कोरिया दौरे पर राजनाथ सिंह, भारत की रक्षा साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती

कोलकाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वियतनाम और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा साझेदारी को मजबूत करना, रणनीतिक सैन्य सहयोग बढ़ाना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा कि वे हनोई पहुंचकर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर रहेगा फोकस

रक्षा मंत्री ने बताया कि इस यात्रा के दौरान उनका ध्यान विशेष रूप से रक्षा सहयोग, सैन्य साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत, वियतनाम और दक्षिण कोरिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देना चाहता है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं और देशों के बीच

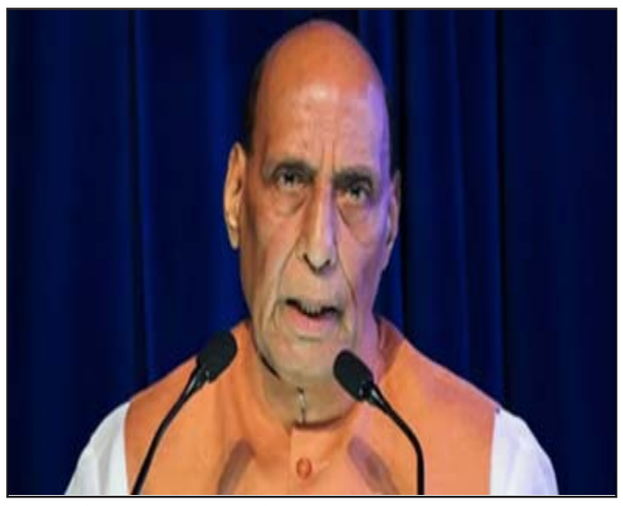

सहयोग की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी में लगातार मजबूती

हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का अहम स्तंभ माना था। दोनों देशों ने रक्षा नीति संवाद, संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी सहयोग, नौसेना बंदरगाह दौरे, रक्षा उत्पादन और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इसके अलावा भारत द्वारा दिए गए रक्षा ऋण लाइनों के तहत वियतनाम की सैन्य क्षमता को मजबूत करने की दिशा में भी प्रगति हुई है।

दक्षिण कोरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी

भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल के वर्षों में अपने संबंधों को आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ाया है। दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और नियम आधारित बनाए रखने के लिए साझा दृष्टिकोण रखते हैं। इस साझेदारी के तहत रक्षा उद्योग, उभरती तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने की योजना है। राजनाथ सिंह का यह दौरा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और हिंद-प्रशांत रणनीति को और मजबूती देगा। इससे क्षेत्रीय देशों के साथ भारत की रक्षा साझेदारी और समुद्री सुरक्षा सहयोग को नई दिशा मिलेगी।

पार्क सर्कस में हिंसा मामले पर सरकार सख्त, 40 गिरफ्तार; सीएम बोले- कानून तोड़ने वाले नहीं बख्शे जाएंगे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कोलकाता पुलिस के दक्षिण-पूर्व डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहर की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। यह बैठक पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा के एक दिन बाद बुलाई गई थी। रविवार को अल्पसंख्यक-बहुल इस इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने बताया कि तिलजला इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर और ईंटें फेंकीं। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पार्क सर्कस हिंसा के मामले में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस ने कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है।

पीएम मोदी के कल्पसर प्रोजेक्ट को मिली नई उड़ान, डच तकनीक से संवरेगा गुजरात का भविष्य

गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे महत्वाकांक्षी सपनों में से एक 'कल्पसर प्रोजेक्ट' को हकीकत में बदलने की दिशा में अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। रविवार को अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मशहूर जल प्रबंधन ढांचे 'अफस्लूटडिक' का बहुत ही बारीकी से दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन भी मौजूद थे। इस दौरे के बाद भारत और नीदरलैंड के बीच कल्पसर प्रोजेक्ट को लेकर एक अहम तकनीकी समझौता भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के इस बांध में इस्तेमाल की गई तकनीक की जमकर तारीफ की और कहा कि यह तकनीक हमारे देश के लिए भी बहुत काम आ सकती है। आपको बता दें कि नीदरलैंड के इस

अफस्लूटडिक बांध और गुजरात में बनने वाले कल्पसर प्रोजेक्ट के बीच बहुत सी समानताएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच कल्पसर प्रोजेक्ट पर तकनीकी सहयोग के लिए एक 'लेटर ऑफ इंटेंट' पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बड़े समझौते से अब गुजरात के इस अटके हुए प्रोजेक्ट के तेजी से पूरा होने का नया रास्ता खुल गया है।

कल्पसर प्रोजेक्ट आखिर है क्या और यह कैसे काम करेगा?

कल्पसर प्रोजेक्ट गुजरात के खंभात की खाड़ी में बनने वाला एक बहुत ही विशाल और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य खंभात की खाड़ी के पास एक बहुत बड़ा बांध बनाना है। इस बांध की मदद से उन सात नदियों के पानी को समुद्र में खारा होने से रोका जाएगा, जिनका मीठा पानी अभी बेकार में समुद्र में बह जाता है। इस पानी को रोककर खाड़ी के अंदर ही एक बहुत बड़ा मीठे पानी का तालाब (रिजर्वायर) बनाया जाएगा। सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट की मदद से बिजली भी बनाई जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी और यातायात के लिए नया रास्ता भी तैयार होगा।

गुजरात के लोगों को इस प्रोजेक्ट से क्या-क्या बड़े फायदे होंगे?

अगर यह कल्पसर प्रोजेक्ट एक बार पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, तो इससे गुजरात के लोगों की किस्मत बदल जाएगी। सौराष्ट्र क्षेत्र के नौ जिलों की 42 तहसीलों की लगभग 10 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन को इस मीठे पानी से सिंचाई का सीधा फायदा मिलेगा। इससे किसानों की फसल अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी जो अभी 240 किलोमीटर है, वह घटकर मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट से 1,500 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी, जिससे बिजली की कमी दूर होगी। नीदरलैंड का अफस्लूटडिक बांध पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन का एक जीता-जागता और बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। करीब 80 साल पहले बनाए गए इस 32 किलोमीटर लंबे बांध ने उत्तरी सागर के खारे पानी को रोककर एक मीठे पानी की झील बना दी है। यह बांध नीदरलैंड के निचले इलाकों को भयानक बाढ़ से भी बचाता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समुद्र के खारे पानी को अंदर आने से रोकता है। इसी तर्ज पर अब गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट में भी नीदरलैंड की इसी 90 साल पुरानी महारत और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल, गुजरात एक ऐसा राज्य रहा है जिसने दशकों तक अनियमित बारिश और भयानक सूखे का सामना किया है। सरदार सरोवर बांध बनने से राज्य को बहुत बड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन भविष्य की पानी की जरूरतों के लिए केवल एक ही प्रोजेक्ट पर निर्भर रहना बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कल्पसर प्रोजेक्ट का सपना देखा था। साल 2004 में उनके ही नेतृत्व में इस बांध की जगह तय करने के लिए भावनगर में एक बहुत बड़ा समुद्री सर्वे भी शुरू किया गया था। लेकिन यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा जटिल था।

न्यूज कैप्सूल

रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, डॉलर के मुकाबले 96.25 तक लुढ़का

मुंबई। भारतीय रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, मजबूत अमेरिकी मुद्रा और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के चलते घरेलू मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.19 प्रति डॉलर पर खुला और जल्द ही 96.25 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया। यह पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले 44 पैसे की गिरावट दर्शाता है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और डॉलर की मजबूती से उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है। इसका असर भारतीय रुपये पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को भी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी के साथ 95.81 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.04 प्रतिशत बढ़कर 99.32 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोरी का माहौल रहा। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 833.20 अंक टूटकर 74,404.79 अंक पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 234 अंक गिरकर 23,401.70 अंक पर कारोबार करता दिखा।

भारतीय शेयर बाजार विभिन्न झटकों को झेलने में सक्षमः सेबी चेयरमैन

नयी दिल्ली।बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ा है लेकिन भारतीय शेयर बाजार विभिन्न तरह के झटके झेल पाने में सक्षम हैं। पांडेय ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाले संकट का असर अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष से तेल आपूर्ति श्रृंखला और कीमतें प्रभावित हुई हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई का जोखिम बढ़ा है। उन्होंने कहा, इस स्थिति का असर सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है और आगे चलकर इसके प्रभाव का प्रसार और परवर्ती प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। हालांकि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख ने भारतीय बाजार की मजबूती पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह इस तरह के झटकों को समाहित कर लेता है और स्थिति सामान्य होने पर फिर से अपनी स्वाभाविक गति पकड़ लेता है। पांडेय ने यह भी स्वीकार किया कि सितंबर, 2024 के बाद से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में कुछ निकासी देखी गई है, लेकिन घरेलू निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर पर बाजार आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उतार-चढ़ाव की स्थिति होना स्वाभाविक है। पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल एवं गैस की आपूर्ति काफी हद तक बाधित हो गई है।

होटल क्षेत्र में जनवरी-मार्च तिमाही में निवेश 58 प्रतिशत बढ़कर 18.5 करोड़ डॉलरः जेएलएल

नयी दिल्ली। भारत के होटल क्षेत्र में इस वर्ष जनवरीदृमार्च तिमाही में निवेश 58 प्रतिशत बढ़कर 18.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। यह होटल कारोबार की वृद्धि संभावनाओं को लेकर निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। जेएलएल इंडिया ने यह जानकारी दी। होटल उद्योग में पिछले वर्ष की समान अवधि में 11.7 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ था। रियल एस्टेट क्षेत्र की सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने होटल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया 2025 शीर्षक से रिपोर्ट सोमवार को जारी की। इसमें कहा गया कि पिछले कैलेंडर वर्ष में निवेश 67 प्रतिशत बढ़कर 56.7 करोड़ डॉलर हो गया था और यह बढ़त जनवरी-मार्च तिमाही में भी जारी रही। रिपोर्ट में कहा गया, 2026 की पहली तिमाही (जनवरीदृमार्च) में असाधारण लेनदेन गतिविधियां देखने को मिलीं, जिसे 2025 से जारी निवेश गति का समर्थन मिला। कुल लेनदेन मात्रा लगभग 18.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर रही जो 2025 की पहली तिमाही के लगभग 11.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है।

सम्पादकीय

न्यायाधीशों का संख्याबल

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह अध्यादेश जारी किया, उससे यह पता चलता है कि वह शीर्ष कोर्ट में शीघ्र ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ते हुए देखना चाहती है। अब मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। निश्चित रूप से इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रणाली में तेजी लाने में सहायता मिलेगी।उम्मीद की जाती है कि इसके चलते सुप्रीम कोर्ट से लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा, लेकिन प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में स्थिति कैसे और कब बदलेगी? आवश्यकता ऐसे उपाय करने की भी है कि उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में भी लंबित मुकदमों का बोझ कम हो और लोगों को समय पर न्याय सुलभ हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या लगभग पांच करोड़ पहुंच गई है।न तो लंबित मुकदमों का बोझ कम हो रहा है और न ही लोगों को समय पर न्याय मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि सामान्य मामलों का निपटारा होने में भी वर्षों और कई बार तो दशकों लग जाते हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्याय में देरी एक तरह का अन्याय ही है।सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, इनमें केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से ही बात बनने वाली नहीं है। यदि समय पर न्याय देना है तो हर स्तर पर न्यायपालिका को पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस भी करना होगा। न्याय में देरी का एक कारण न्यायाधीशों की कमी ही नहीं, बल्कि संसाधनों का अभाव भी है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर गंभीरता से विचार इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने देश में प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग 22 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं।इसके विपरीत विकसित देशों में प्रति दस लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या सौ से अधिक है। दशकों पहले विधि आयोग ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रति दस लाख आबादी पर कम से कम 50 न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता जताई थी।कोई नहीं जानता कि इस आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं की जा पा रही है? समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया के तौर-तरीके बदलें। इसके अतिरिक्त, कार्यपालिका अपने लोगों के खिलाफ मुकदमे करने की प्रवृत्ति का परित्याग करे। यदि यह सब नहीं किया जाता तो तारीख पर तारीख का सिलसिला थमने वाला नहीं है।

मुख्यमंत्रियों के चुनाव हारने की परंपरा

जयसिंह रावत

सत्ताधारी मुख्यमंत्री का अपनी ही विधानसभा सीट गंवा देना भारतीय राजनीति का एक रोचक और जटिल पहलू है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर हालिया चुनावी उथल-पुथल तक, यह सिलसिला लोकतंत्र की एक ऐसी गाथा सुनाता है जहां जनता की खामोशी सत्ता के अहंकार से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती है। भारतीय संसदीय इतिहास में मुख्यमंत्रियों के हारने की परंपरा पुरानी है, जो यह दर्शाती है कि यहां की लोकतांत्रिक जड़ें व्यक्ति विशेष के कद से हमेशा गहरी रही हैं। इसकी शुरुआत 1971 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह की मनीराम सीट पर हुई हार से हुई थी, जिसने देश को पहली बार यह अहसास कराया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। इसके बाद समय-समय पर बड़े नाम इस सूची में जुड़ते गए।शिबू सोरेन का 2009 के उपचुनाव में तमाड़ सीट से हारना एक बड़े राजनीतिक संकट के रूप में उभरा, क्योंकि वह निर्वाचित हुए बिना मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। इसी तरह बंगाल में 34 वर्षों के वामपंथी शासन के पतन की सबसे बड़ी मुहर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की 2011 में जाधवपुर सीट पर हुई हार थी। उत्तराखंड की भूमि पर भी जनता ने बार-बार यह संदेश दिया है। 2012 में भुवन चंद्र खंडूड़ी का कोटद्वार से हारना और 2017 में हरीश रावत का हरिद्वार ग्रामीण एवं किच्छा जैसी दोनों सीटों से पराजित होना इसी लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक है। 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार से पराजित हुए, जबकि उनकी पार्टी भाजपा राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी कर रही थी। ये रुझान दर्शाते हैं कि सत्ता की चमक कभी भी मतदाता की मूल अपेक्षाओं और उसके स्वाभिमान के सामने टिक नहीं पाती।किसी मुख्यमंत्री की हार के पीछे अक्सर सबसे बड़ा कारण उनका अति-आत्मविश्वास और सत्ता का अहंकार होता है। जब कोई नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है या भारी बहुमत से जीतता है तो अक्सर वह जनता की नब्ज टटोलने के बजाय अपनी इच्छाएं जनता पर थोपना शुरू कर देता है। जनता की भावनाओं को समझने के बजाय जब अपनी मनमानियों को जनमानस पर लादने की कोशिश करते हैं तो वहीं से उनके पतन की पटकथा लिखी जाती है। 2017 में हिमाचल के प्रेम कुमार धूमल की सुजानपुर में हार हो या गोवा के लक्ष्मीकांत पारसेकर की मंड्रेम में शिकस्त के पीछे जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और सत्ता का बढ़ता हुआ केंद्रीकरण था। जब जनता को यह लगने लगता है कि उनका सेवक अब उनका शासक बनने की कोशिश

कर रहा है तो वह मतदान केंद्र पर चुपचाप अपनी ताकत दिखा देती है।हाल के वर्षों में, विशेषकर 2021 से 2026 के मध्य, चुनाव में मुख्यमंत्रियों की हार के पैटर्न ने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। बंगाल के 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी से मात खा गईं। ममता बनर्जी ने उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, लेकिन जनता ने यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष को अपनी जागीर नहीं समझ सकता। पंजाब में 2022 के चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी का अपनी दोनों सीटों, चमकौर साहिब और भदौड़ से हारना सत्ता के प्रति जनता के तीव्र मोहभंग का परिणाम था। 2024 में ओडिशा के अजेय माने जाने वाले नवीन पटनायक का कांटाबांजी सीट से हारना और 24 साल के शासन का अंत होना, इस बात का प्रमाण है कि जनता एक समय के बाद बदलाव और नई ऊर्जा चाहती है।2026 के ताजा चुनावी परिणामों ने इस फेहरिस्त में सबसे चौंकाने वाले अध्याय जोड़े हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते एमके स्टालिन का अपनी अभेद्य मानी जाने वाली कोलाथुर सीट पर एक नवोदित दल टीवीके के प्रत्याशी से लगभग 9,000 वोटों से हारना यह दर्शाता है कि दक्षिण की राजनीति में भी द्रविड़ किले में दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर हार और सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग की पूर्व में पराजय यह साबित करती हैं कि चेहरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह काम और व्यवहार का विकल्प नहीं हो सकता। कर्नाटक में सिद्दरमैया की चामुंडेश्वरी में हार भी इसी अहंकार की बलि चढ़ने का उदाहरण थी। मुख्यमंत्रियों की हार को देखते हुए बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह निजी असफलता है या व्यापक राजनीतिक संकेत? वस्तुतः देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों की हार के सवाल का उत्तर एक से अधिक आयामों में छिपा है। कई बार स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, उम्मीदवार चयन में हुई चूक, गुटबाजी या विपक्षी उम्मीदवार की मजबूत अपील इसका कारण बनती है। यह राजनीतिक दलों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता के भरोसे अकेले चुनाव नहीं जीते जा सकते। जमीनी संगठन, स्थानीय मुद्दों की समझ और उम्मीदवार की छवि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वहीं यह सत्ता विरोधी आक्रोश भी है, क्योंकि यह शासकों को चेतावनी देता है कि वे जनता की भावनाओं को हल्के में न लें। जब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग जनता का मन टटोलना बंद कर देते हैं और अपनी नीतियां या अपनी सनक को उन पर थोपते हैं तो जनता का गुस्सा शांत, लेकिन प्रभावी ढंग से फूटता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सत्ता के साथ साख भी गंवाई

राज कुमार सिंह

वैसे तो हार-जीत एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं, लेकिन अगर आपके हिस्से अक्सर एक ही पहलू आए तो गंभीर आत्मविश्लेषण की जरूरत है। हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों ने इस पहलू को फिर से रेखांकित किया है। असम में भाजपा की हैटट्रिक को लेकर शायद कांग्रेस को भी संदेह नहीं रहा होगा। खासकर 2023 के परिसीमन के बाद सामाजिक समीकरणों पर भाजपा की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि वहां उसकी सत्ता को हिलाना फिलहाल तो आसान नहीं है।अपनी आक्रामक भाषा और राजनीतिक प्रबंधन से भी अपनी उपयोगिता साबित कर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा आलाकमान के लाड़ले बन गए हैं। न सिर्फ असम, बल्कि समूचे पूर्वोत्तर में भाजपाई सत्ता विस्तार में हिमंत की अहम भूमिका रही। इसे देखते हुए क्या कांग्रेस को ऐसे उपयोगी नेता को गंवाने पर कोई अफसोस होता है या नहीं?

यह भी न भूला जाए कि कांग्रेस सरकारों में वरिष्ठ मंत्री रहे हिमंत ने राहुल गांधी के व्यवहार से खफा होकर ही कांग्रेस छोड़ी थी। राहुल गांधी की टिप्पणियों से तो नहीं लगता कि ऐसे उपयोगी और जनाधार वाले नेताओं के अलगाव पर कांग्रेस में कोई आत्मचिंतन चल रहा है। बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की सत्ता का 15 साल पुराना मजबूत किला ध्वस्त हो गया। देखा जाए तो ममता और उन्हें सत्ता से अपदस्थ करने में अहम भूमिका निभाने वाले सुवेंदु अधिकारी दोनों ही मूलतः कांग्रेसी हैं।पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने एन. रंगासामी भी पुराने कांग्रेसी ही हैं, जिन्होंने अलग क्षेत्रीय पार्टी बना कर भाजपा से गठबंधन में दूसरी बार जनादेश हासिल किया है। यह कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक समझ और प्रबंधन के फर्क को भी रेखांकित करता है। कांग्रेस जहां ऐसे उपयोगी नेताओं को मान-सम्मान नहीं दे पाती, वहीं भाजपा उन्हें दूसरे दलों से भी लाकर अपने यहां समाहित कर लेती है। इस बार अकेले बहुमत मिलने के बावजूद भाजपा ने असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट जैसे मित्र दलों को संक्षिप्त मंत्रिमंडल गठन में भी स्थान दिया है, जबकि कांग्रेस के मित्र दलों की नाराजगी असम में भी मुखर होने लगी है।कांग्रेस बंगाल में लगभग सभी सीटों पर जीतने के बाद दो पर जीत हासिल करने में भी सफल रही, लेकिन इससे विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए की साख और भविष्य पर भी सवाल उठने लग गए। बेशक इसके लिए ममता बनर्जी की जिद भी उतनी ही जिम्मेदार रही, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल के विधानसभा चुनाव में भी सहयोगी दलों को कोई भाव नहीं दिया। आइएनडीआइए का यह विरोधाभास भी किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर साथ होते हुए भी केरलम में कांग्रेस और वाम मोर्चा आमने-सामने होते हैं। इस बार वहां कांग्रेसनीत यूडीएफ ने एलडीएफ यानी वाम मोर्चा से ही सत्ता छीनी है। बंगाल में तो यह विरोधाभास

और भी विचित्र है। ममता ने कांग्रेस छोड़कर ही अलग तृणमूल कांग्रेस बनाई और अकेले दम पर 2011 में 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को उखाड़ फेंका।यह विरोधाभास ऐसा राजनीतिक सच है, जिससे मुंह नहीं चुराया जा सकता। फिर भी राहुल गांधी चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध भाजपाई भाषा-शैली के उपयोग से बच सकते थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा नेता ममता शासन के लिए 'टीएमसी का गुंडाराज' जैसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। उसी शब्दावली का उपयोग करते हुए राहुल ने अप्रत्याशित रूप से संक्षिप्त चुनाव प्रचार में आरोप लगाया कि ममता ने ठीक से सरकार नहीं चलाई, इसलिए बंगाल में भाजपा के लिए रास्ता खुल रहा है। भाजपा को 207 और तृणमूल को 80 सीटें देकर बंगाल के मतदाताओं ने अपना निर्णय सुना दिया तो राजनीतिक अवसरवाद फिर दिखाई पड़ा, जब ममता और राहुल दोनों के सुर बदल गए।राहुल ने चिरपरिचित अंदाज में आरोप लगाया कि असम और बंगाल दोनों जगह चुनाव चोरी किया गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीचे से खिसकते ही तृणमूल सुप्रीमो की ममता भी आइएनडीआइए के लिए सहानुभूति जाग उठी। किस-किस घटक दल नेता ने फोन किया और मुलाकात की, इसका विवरण मीडिया से साझा करते हुए ममता ने आह्वान किया कि भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस और वाम दलों समेत सभी को साथ आना चाहिए। स्वाभाविक ही है कि वाम मोर्चा और कांग्रेस ने इस आह्वान पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आक्रामक राजनीति से भाजपा के बढ़ते सत्ता-वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इसके बावजूद यह तय दिख रहा है कि परस्पर राजनीतिक शह-मात का खेल भी जारी रहेगा।चुनाव परिणाम के बाद मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर प्रक्रिया के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जाना समझ में आता है, पर हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने की हठ से गया नकारात्मक संदेश विपक्ष की साख पर बड़ा सवालिया निशान लगा गया है। तमिलनाडु में द्रमुक के सत्ता से बेदखल होते ही कांग्रेस ने अभिनेता विजय की टीवीके को सरकार गठन के लिए समर्थन देने में देर नहीं लगाई। दशकों पुराने मित्र द्रमुक का इससे आहत होना स्वाभाविक है, लेकिन सत्ता राजनीति तो है ही विशुद्ध अवसरवाद का खेल। अन्यथा जिस द्रमुक के विरुद्ध अन्नाद्रमुक बनी, सरकार गठन के लिए उसी से हाथ मिलाने की संभावनाएं नहीं टटोली जातीं। अवसरवाद की उसी पराकाष्ठा का परिणाम है कि अन्नाद्रमुक दो फाड़ हुई और बड़े गुट ने विश्वासमत परीक्षण में नवगठित विजय सरकार का समर्थन किया। बेशक अतीत में भी चुनाव से सिर्फ सत्ता नहीं, राजनीतिक समीकरण भी बदलते रहे हैं, लेकिन पांच राज्यों के इन चुनावों में विपक्ष खासकर आइएनडीआइए ने सत्ता के साथ-साथ साख भी गंवा दी है और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में दोनों ही वापस हासिल कर पाना आसान नहीं लगता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

ओ पी की विकासपरक राजनीति बनाम सिंदूर पार्क ऑक्सीजोन

मुकेश जैन

किसी शहर का सर्वांगीण विकास एक जटिल और श्रम-साध्य मसला है, विशेषकर किसी पुराने बसाहट वाले शहर का व्यवस्थित विकास बहुत ही पेचीदा होता है। इसके लिये शहरवासियों की जरूरतों की ठीक-ठीक समझ, वहाँ की पारिस्थितिक विशेषताओं, सांस्कृतिक परिवेश, परंपराओं व विरासत के साथ संतुलन स्थापित करना , इसके ठीक समानांतर आधुनिक भविष्य की जरूरतों के साथ भी तालमेल कायम रख पाना और इन सबके बीच ठोस व समयबद्ध कार्ययोजना का निर्माण तथा योजनाओं को धरातल पर उतारने का आवेगपूर्ण संकल्प, सभी का एकजायी होना आवश्यक होता है। यह सुखद संयोग है कि रायगढ़वासियों को इन सभी विशिष्ट योग्यताओं से परिपूर्ण ओ पी चौधरी का कुशल नेतृत्व मिला है और इस अंचल से दिली-लगाव रखने वाले विष्णु देव साय मुख्यमंत्री के रूप में हमारे साथ हैं। कहते हैं कि जब नेतृत्व सबल, नियत साफ और सोच बड़ी हो तो जनता के सपनों को न केवल पंख लग जाते हैं वरन एक-एक करके सपने साकार भी होने लगते हैं। रायगढ़ में विगत ढाई वर्षों से चल रहे विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला इसकी बानगी है। इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शहर के हृदय स्थल में नवनिर्मित बेहतरीन ऑक्सीजोन कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के करकमलों से आमजनता को अर्पित हुआ है। निश्चित रूप से यह अवसर रायगढ़ के नव-विकास के शिल्पी ओ पी चौधरी की पीठ थपथपाने और हमारे लाड़ले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करने का क्षण है। यह रायगढ़ के चेहरे पर एक मीठी व लम्बी मुस्कान बिखरने का क्षण है।

अतीत की उपेक्षा और नया संकल्प- जब हम रायगढ़ के अतीत पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि मध्यप्रदेश के धूर-पूर्वी छोर का अंतिम शहर होने के कारण हमारा रायगढ़ दशकों तक भोपाल में बैठे नीति-निर्धारकों की दृष्टि से लगभग ओझल ही रहा। रायगढ़ को 1901 में नगरपालिका परिषद का दर्जा मिला। तब से लेकर 2001 तक 100 वर्षों के लंबे कालखण्ड में रायगढ़ बेहद मंथर गति से यात्रा करता रहा। मध्यप्रदेश के बड़े शहरों की ओट में दुबक कर रायगढ़ यथास्थिति में रहने का अभिशाप झेलता रहा। हमारे आस-पास के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग भी विकास के मामले में हमसे काफी आगे निकल गये। अटल जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दिये जाने के बाद परिस्थितियां बदली। 2002 में रायगढ़ को निगम का दर्जा हासिल हुआ। 2003 में नये नेतृत्व को काम करने का मौका मिला और रायगढ़ उपेक्षा के दौर से बाहर निकलकर विकास की दहलीज छूने लगा। इस दौर में कतिपय उल्लेखनीय काम जरूर हुये लेकिन 100 वर्षों के बैकलॉग के सामने ये नाकाफी थे। चूंकि लंबे समय की जड़ता थी इसलिये विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये फुटकर प्रयासों से काम नहीं चलने वाला था। उसे एकमुश्त बड़ी छलांग लगाने की जरूरत थी और इस सिद्धि के लिये रायगढ़ किसी ताकतवर एवं सक्षम उद्धारक की बांट जोह रहा था। उनकी वर्षों की यह तलाश ओ पी चौधरी तक आकर पूर्ण हुई है। रायगढ़ के वृहत काया-कल्प हेतु चल रहे सौ से अधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स और उन पर ताबड़-तोड़ एक्शन इस बात के जीवंत प्रमाण हैं। विगत दो-ढाई वर्षों के अनथक क्रियाकलापों से ओ पी ने 'एक ही राजनीति- विकास की राजनीति' के मूलमंत्र को कार्य रूप में सिद्ध करके दिखाया है।

विकास अपने-आप में एक विस्तृत व बहुआयामी अवधारणा है। ओ पी चौधरी के लिये विकास का आशय केवल बड़े व मेगा प्रोजेक्ट्स को मूर्तरूप देने तक सीमित नहीं है वरन आम लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन का उत्थान व जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव उनके लिये विकास का असली पैमाना है।

विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला- नालन्दा परिसर, केलो-नहर निर्माण,

प्रस्तावित रिंग रोड, मेरीन ड्राइव, स्टेडियम का उन्नयन, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, प्रयास विद्यालय, आधुनिक बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन का आधुनिकीकरण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, सीवरेज, सड़क, पुल-पुलियों के साथ ही पहाड़ मंदिर का ईको-सेंटर की तर्ज पर विकास , उर्दना में नगर -वन की स्थापना और शहर के चारों ओर अलग-अलग ऑक्सीजोन का निर्माण यह दर्शाता है कि ओ पी चौधरी लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण बदलाव को लेकर कितने संजीदा हैं।

बहुपयोगी सुविधाओं से लैस ऑक्सीजोन

शहर के बीचों- बीच इतवारी बाजार और कृषि-उपज मंडी का बड़ा भूखंड लगभग अनुपयोगी सा पड़ा था। इस पर कभी मल्टीस्टोरी शापिंग काम्प्लेक्स व मल्टी लेबल आधुनिक पार्किंग की योजना बनी और कभी ऑडिटोरियम निर्माण की योजना बनी लेकिन विभिन्न विभागों में सामंजस्य की कमी और राजनीतिक अड़ंगेबाजी के कारण कोई भी योजना परवान नहीं चढ़ सकी। इस बेशकीमती भूखंड का व्यावसायिक उपयोग करके शासन इसे बड़े आर्थिक रिटर्न व एक नियमित आय का जरिया बना सकती थी लेकिन ओ पी चौधरी ने इसे आम जनता के हितार्थ ऑक्सीजोन के लिये चुना और इसके बहुपयोगी स्वरूप की परिकल्पना की तो उसके पीछे गहरी सोच व गूढ़ निहितार्थ हैं।

शहर के आस-पास उद्योगों की स्थापना, शहर के भीतर वृहत कांक्रीटीकरण और बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही आदि कारणों से शहर में कार्बनडाइऑक्साइडका स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है। अलग-अलग स्थानों में ऑक्सीजोन के निर्माण के द्वारा ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना आम तौर पर पर्यावरणीय संतुलन कायम करने का एक समाधानकारक व बेहतर विकल्प होता है। नवनिर्मित ऑक्सीजोन में विशेषज्ञों की सलाह पर अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले पेड़-पौधे लगाये गये हैं, बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले-फिसलपट्टी आदि की व्यवस्था है, योग हेतु अलग मंच, ओपन एयर थिएटर सहित वॉकिंग ट्रैक भी है। इससे लगकर एक गेम- जोन व फूडकोर्ट और व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण भी किया गया है। संक्षेप में, जहां एक ओर यह ऑक्सीजोन काफी हद तक प्रदूषण से राहत देने वाला केंद्र होगा वहीं दूसरी ओर यह सैर-सपाटे, योग, स्वच्छ हरित पट्टिका, वॉकिंग, कला मंचन आदि की सुविधाओं से लैस उपयोगी स्वास्थ्य केंद्र , कम्युनिटी मीटिंग और कलात्मक व सांस्कृतिक मेल-जोल के केंद्र के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री साय की मंशा के अनुरूप हुआ नामकरण -

इस ऑक्सिजोन के साथ एक विशिष्ट और उल्लेखनीय विषय इसके नाम का चयन भी है। विदित हो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा काश्मीर घाटी में भारतीय महिलाओं के सामने ही उनका सिंदूर मिटा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी नेतृत्व में भारतीय सेना ने अद्भूत शौर्य का प्रदर्शन करते हुये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को ऐसा मुँह-तोड़ जवाब दिया था कि पूरा विश्व अचंभित हो गया। ऑक्सीजोन का नाम सिंदूर पार्क रखकर न केवल उस आतंकी घटना में शहीद हुये 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों को एक विनम्र श्रद्धांजलि दी गयी है वरन यह उन बहनों को भावपूर्ण संदेश भी है कि देशवासी उनके पतियों के बलिदान को भूले नहीं हैं। यह नामकरण भारतीय सेना के तीनों विंग के जवानों व महिला सैनिकों के अदम्य साहस को एक गर्वीला सैल्यूट भी है। एक पार्क को इस तरह से एक राष्ट्रीय संदर्भ से जोड़ देने के पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अभिनव सोच मुख्य कारक बनी। इसके लिये वे साधुवाद के पात्र हैं।

कंटीले रास्तों पर चलकर मिला है ऑक्सीजोन- किसी पुराने शहर में एक स्थापित स्थल के परंपरागत उपयोग को परिवर्तित करना जोखिम भरा कदम होता है। इसके लिये अनेक तरह-तरह के आरोपों व उलाहनों का सामना करना पड़ता है। इतवारी बाज़ार ऑक्सीजोन के निर्माण को भी इसी तरह के कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा है। चूंकि योजना के मूल में व्यापक जनहित की स्पष्ट मंशा काम कर रही थी अतः आरंभिक अड़चनों के बावजूद जब योजना ने मूर्त-रूप ले लिया तो रायगढ़ के बाशिंदों ने बाँहे फैलाकर इसका स्वागत करने में भी कोई कंजूसी नहीं दिखाई है । आज चौक-चौराहों में ओ पी चौधरी के इस पहल की दिल खोलकर प्रशंसा हो रही है।

इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका - आज यदि हम कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, एस डी एम महेश शर्मा, नगर निगम के कर्मठ व सक्रिय आयुक्त बृजेश क्षत्रिय व हाऊसिंग बोर्ड के ई.ई. अभिषेक मोहन तिवारी को याद नहीं करेंगे तो ऑक्सीजोन निर्माण की कहानी अधूरी रह जायेगी। तमाम तरह के झंझावातों से जूझकर इसे पूरा करना बहुत ही कठिन व दुरूह टास्क था। यह दुष्कर कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण होकर यदि आज जनता को समर्पित हो पाया है तो इसके पीछे इन अधिकारियों की दिन-रात की मेहनत है। वे भी इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

मियावकी वन तकनीक से हरित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम

धनंजय राठौर,अशोक कुमार चंद्रवंशी

वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मियावाकी तकनीक एक बेहद प्रभावी और लोकप्रिय विधि बन गई है। जापानी वनस्पतिशास्त्री डॉ. अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित यह तकनीक केवल 2-3 वर्षों में बंजर भूमि को घने, आत्मनिर्भर सूक्ष्म वनों में बदल देती है। पारंपरिक वृक्षारोपण की तुलना में यह विधि 10 गुना तेजी से बढ़ती है और 30 गुना अधिक घने जंगल बनाती है, जो शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श है। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मियावकी वन तकनीक तेजी से अपनाई जा रही है। राज्य में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस तकनीक के जरिए शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और खनन प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर हरियाली विकसित की जा रही है। मियावकी पद्धति में स्थानीय प्रजातियों के पौधों को अधिक घनत्व में लगाया जाता है, जिससे मात्र 3 से 5 वर्षों में घना जंगल तैयार हो जाता है।

राज्य में तेजी से बढ़ रहा सघन वनीकरण

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 से मियावकी पद्धति के तहत लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2022 में कोटा मण्डल में एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 23 हजार पौधे तथा 0.3 हेक्टेयर में 7 हजार पौधे लगाए गए। वर्ष 2023 में कोटा के भिल्मी क्षेत्र में 6.4 हेक्टेयर भूमि पर 64 हजार पौधों का रोपण किया गया। वहीं गेवरा क्षेत्र में 2 हेक्टेयर भूमि पर 20 हजार पौधे लगाए गए। वर्ष 2024 में कोटा के उच्चभट्टी क्षेत्र में 3.2 हेक्टेयर में 32 हजार पौधे लगाए गए। इसके अलावा रायगढ़ मण्डल के तिलईपाली और छाल क्षेत्रों में कुल 3.75 हेक्टेयर भूमि पर 37 हजार 500 पौधों का सफल रोपण किया गया।

वर्ष 2025 में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जारी

वर्तमान में राज्य के कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य तेजी से जारी है। बारनवापारा मण्डल में 'हरियर छत्तीसगढ़ऽ योजना के तहत 6 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं। कोरबा और रायगढ़ क्षेत्रों में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सहयोग से 4 हेक्टेयर क्षेत्र में 40 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है। वहीं विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत महानदीकोलफील्ड लिमिटेड द्वारा 1.9 हेक्टेयर भूमि पर 64 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अरपा नदी के किनारे भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर हरित क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण में मिल रहे बहुआयामी लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार मियावकी वन सामान्य जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। यह तकनीक वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने, भू-जल स्तर सुधारने और मिट्टी संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन वनों की शुरुआती वर्षों में देखभाल की जाती है, जिसके बाद ये जंगल स्वतः विकसित होने लगते हैं। इससे रखरखाव की लागत कम होती है और लंबे समय तक पर्यावरणीय लाभ मिलता है।

बंजर डंप क्षेत्र से हरित जंगल बनने की ओर गेवरा की प्रेरक पहल

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए कोरबा जिले के गेवरा क्षेत्र के 12.45 हेक्टेयर डंप क्षेत्र में 33 हजार 935 मिश्रित प्रजातियों के पौधों का सफल रोपण किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

जहां हरियाली संभव नहीं थी, वहां तैयार हो रहा जंगल

कोयला खनन के बाद डंप क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी नीचे दब जाती है और ऊपर पत्थर, कोयला अवशेष तथा अनुपजाऊ मिट्टी रह जाती है। ऐसे क्षेत्रों में पौधों का उगना बेहद कठिन माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति और सतत प्रयासों से इस बंजर भूमि को अब हरियाली में बदला जा रहा है।

वैज्ञानिक तरीके से किया गया पौधारोपण

डंप क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट, नीमखली और डीएपी का उपयोग किया गया। जीपीएस सर्वे और सीमांकन के बाद व्यवस्थित गड्ढे तैयार किए गए तथा 3 से 4 फीट ऊंचाई वाले स्वस्थ पौधों का रोपण किया गया। इस क्षेत्र में नीम, शीशम, सिरस, कचनार, करंज, आंवला, बांस, महोगनी, महुआ और बेल जैसी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इससे आने वाले समय में यह क्षेत्र पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के लिए भी उपयुक्त आवास बन सकेगा।

निरंतर देखभाल से मिल रही सफलता

शुरुआती 2-3 वर्षों की देखभाल के बाद, यह वन पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है और इसे किसी उर्वरक या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। रोपण के बाद पौधों की नियमित सिंचाई, खाद, निंदाई-गुड़ाई, घास कटाई और सुरक्षा का कार्य लगातार किया जा रहा है। मृत पौधों का समय पर प्रतिस्थापन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2025 से 2029 तक पांच वर्षों तक रखरखाव के बाद इस विकसित हरित क्षेत्र को साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गेवरा को सौंपा जाएगा।

हरित भविष्य की ओर मजबूत पहल

कम जगह में घने जंगल बनाकर शहरों में प्रदूषण (धूल और ध्वनि) को कम करने में सहायक होते हैं। ये वन पारंपरिक वनों की तुलना में 30 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। गेवरा की यह पहल दर्शाती है कि सही योजना, वैज्ञानिक तकनीक और निरंतर प्रयासों से बंजर और पत्थरीली भूमि को भी घने जंगल में बदला जा सकता है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र सघन हरित वन और जैव विविधता से भरपूर मानव निर्मित जंगल के रूप में विकसित होगा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा।

लेखक संयुक्त संचालक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं।

→→→ न्यूज डायरी ←←←

लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल पर

मलिहाबाद बार एसोसिएशन ने यायिक कार्य बंद रखने का निर्णय लिया

लखनऊ (यूएनएस)। मलिहाबाद बार एसोसिएशन ने लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। सोमवार को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सम्राट सिंह और महामंत्री कमलेश कुमार ने एक ज्ञापन जारी कर बताया कि बीते 17 मई को लखनऊ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ की गई बर्बरता और लाठीचार्ज अशोभनीय था। इस घटना से अधिवक्ताओं में भारी रोष है। बैठक में अधिवक्ता और कर्मचारियों के साथ हो रही अभद्रता एवं अन्य समस्याओं के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहने पर सहमति बनी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 18 मई से 20 मई 2024 तक न्यायिक कार्य पूरी तरह बंद रहेगा। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ अधिवक्ता नमन यादव, अधिवक्ता सतोम सिंह, अधिवक्ता देवेंद्र सिंह, अधिवक्ता अलीशान, संजीत सिंह, रिलेश यादव सहित अन्य पदाधिकारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे।

वकीलों ने बंद कराया डीएम ऑफिस, अफसरों की गाड़ियां भी रोकीं

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी में वकीलों ने आज, सोमवार को डीएम ऑफिस बंद करा दिया। स्वास्थ्य भवन चौराहे से कलेक्ट्रेट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अफसरों-कर्मचारियों की गाड़ियों को भी नहीं जाने दिया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भी बैरिकेडिंग कर दी। वकीलों ने 3 दिन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। वकील कलेक्ट्रेट में घूम-घूमकर सरकारी कार्यालयों को बंद कराया। इससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ। मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के वकीलों ने 2 दिन कार्य बहिष्कार का ऐलान करके तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। दरअसल, रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर नगर निगम ने कचेहरी के आसपास बने वकीलों के अवैध चौंबर व दुकानें तोड़ी थीं। इस दौरान पथराव और लाठीचार्ज हुआ था। इस कार्रवाई से वकील नाराज हैं। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकीलों ने रास्ता बंद कर दिया है। स्वास्थ्य भवन चौराहे से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रास्ता बंद है। इधर से अधिकारियों और आम लोगों को भी कलेक्ट्रेट की ओर नहीं जाने दे रहे हैं। मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशलेंद्र शुक्ला और महामंत्री राम लखन यादव के नेतृत्व में वकीलों ने दो दिनों के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। वकीलों ने मोहनलालगंज तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया और चैंबर तोड़े जाने की घटना की कड़ी निंदा की। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से वकीलों में भारी रोष है और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट शिव अटल सिंह, श्रवण यादव, केपी सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

आशियाना में 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद

लखनऊ (यूएनएस)। आशियाना थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह बाइक सवार तीन चोरों ने तीन दुकानों को निशाना बनाया। बदमाशों ने हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पीड़ित मनीष कुमार मौर्य, निवासी रुचि खंड-1, शारदा नगर, ने बताया कि उनकी फोटो स्टूडियो और जनसेवा केंद्र की दो दुकानें हैं। इनमें से एक दुकान बंगला बाजार पुलिस चौकी के पास स्थित है, जबकि दूसरी सालेह नगर तिराहा स्थित राहुल मार्केट में है। मनीष के अनुसार, सोमवार देर रात करीब तीन बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी दोनों दुकानों के शटर के ताले टूटे हुए हैं। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां डायल-112 पुलिस पहले से मौजूद थी। दुकानों की जांच करने पर पाया गया कि गल्लों के ताले भी तोड़े गए थे और उनमें रखी नकदी चोरी हो गई थी। पीड़ित के मुताबिक, सालेह नगर स्थित दुकान से लगभग 15 से 16 हजार रुपये, जबकि बंगला बाजार स्थित दुकान से करीब 20 हजार रुपये चोरी हुए हैं। मनीष ने यह भी बताया कि उनकी दुकान के पास ही उनके एक मित्र की दुकान है, जिसे भी चोरों ने निशाना बनाते हुए वहां से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात इलाके में बाइक सवार तीन युवक घूमते हुए दिखाई दिए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी तीन युवक मोटरसाइकिल से आते और दुकानों के पास रुकते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारियों ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

चिनहट पुलिस ने किया दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ के पूर्वी जोन अंतर्गत चिनहट थाना पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चिनहट पुलिस महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। बीते लगभग दो महीनों में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अपराधों से जुड़े दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। यह कार्रवाई दीक्षा शर्मा के कुशल मार्गदर्शन और अमोल मुरकुट के दिशा निर्देशन में की गई। विनय द्विवेदी के निकट पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व वाली चिनहट पुलिस टीम को यह सफलता मिली। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ चिनहट पुलिस आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रखेगी।

लखनऊ मेट्रो फेज-1बी के लिए त्रिपक्षीय एमओयू मंजूर

लखनऊ (यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से वसंतकुंज के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के मध्य त्रिपक्षीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस परियोजना की डीपीआर को पहले ही कैबिनेट ने अनुमोदित किया जा चुका था और अब 5801.05 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर सहमति दी गई है। परियोजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी होगी। चारबाग से वसंतकुंज तक बनने वाला यह ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा तथा नागरिकों को आधुनिक और सुगम सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा। लखनऊ मेट्रो फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की डीपीआर को 5 मार्च 2024 को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को परियोजना की कुल लागत 5801.05 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान करते हुए परियोजना का अनुमोदन किया था। भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में यह शर्त रखी गई थी कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय एमओयू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना,यूपी के छोटे गांवों तक बसों का संचालन

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना' पर गंभीरता से ध्यान दे रही है। इसका उद्देश्य छोटे से छोटे गांव तक बसों की पहुंच को बढ़ाना है। राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने तैयारी को तेज कर दिया है। इस योजना के तहत 80 बसों का संचालन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में 59 हजार से अधिक ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ने के लिए सरकार और निगम तेजी से काम कर रहा है। योजना के तहत ग्रामीणों के लिए बस सेवा को ब्लॉक, ग्राम पंचायत, तहसील और जिला मुख्यालय तक जोड़ा जाना है।यूपीएसआरटीसी सहायक प्रबंधक उमेश आर्य ने बताया कि अब तक 70 जिलों के लिए 858 बस ऑपरेटरों के आवेदन चयनित हो चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना' के तहत लगभग 80 बसों का संचालन शुरू हो गया है अधिकतम 28 सीटों वाली मिनी बसें चलाई जानी हैं।

संविधान और धर्मनिरपेक्षता से समझौता देशहित में नहीं, पश्चिम बंगाल हिंसा पर मायावती की सरकारों को नसीहत

लखनऊ (यूएनएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान, संविधान की मर्यादा और पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों को नसीहत दी है। मायावती ने कहा कि भारत की वैश्विक पहचान बाबा साहब के संविधान और सेक्युलर मूल्यों के कारण है, इसलिए सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी प्रकार के धार्मिक, जातीय या राजनीतिक भेदभाव से बचें तथा सभी नागरिकों की जान-माल और मजहबी आजादी की समान रूप से रक्षा सुनिश्चित करें। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जैसा कि सर्वविदित है कि अपने भारत देश की दुनिया भर में अच्छी एवं अनोखी मानवतावादी पहचान खघसकर परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के अनुपम संविधान को लेकर ज्यादा है, जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) के सिद्धान्त पर आधारित है अर्थात् यहां रहने वाले विभिन्न धर्मों के मानने वाले सभी लोगों को एक-समान आदर-सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि देश का मिजाज भी अधिकतर ऐसे ही उच्च मानवीय गुणों पर आधारित सभी धर्मों के मानने वालों को उनके जान, माल व मजहब की आजादी एवं सुरक्षा आदि सुनिश्चित करता है। इसके निर्धारित व बताये हुये रास्तों पर चलना सभी सरकारों की ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों की भी परम व प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि यह भी सर्वविदित ही है कि यही वह सुरक्षा कवच है जिसके सहारे विदेशों में भारत-विरोधी प्रोपागण्डा आदि का देश हमेशा बखघूबी सामना करता है, किन्तु केन्द्र व सभी राज्य सरकारों का यह दायित्वध्जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसा कुछ भी ना करें और ना ही वैसे कुछ होने दें जिससे देश व खघसकर भारत सरकार से इसके बारे अप्रिय सवाल-जवाब हो। उन्होंने कहा कि खघसकर पश्चिम बंगाल में चुनाव उपरान्त

जारी हिंसा की सर्वत्र हो रही चर्चाओं में भी विशेषकर मा. हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सरकारों को इसके प्रति सतर्क व अराजकता के विरुद्ध सख्त हो जाना चाहिये, ताकि किसी भी सरकार के ऊपर संकीर्ण राजनीति, धार्मिक भेदभाव, जातीय द्वेष व पक्षपात आदि का दोष लगे, यह अति-चिन्ता की बात जरूर होनी चाहिये। मायावती ने कहा कि इसके साथ ही, व्यापक जनहित व जनसुरक्षा के मद्देनजर स्थापित नियम-कानूनों के अनुपालन या तत्सम्बंधी नये कघनून आदि बनता है तो उसका अनुपालन सभी धर्मों के लोगों पर एक समान रूप में होना चाहिये अर्थात् संविधान व कघूनन की मान-मर्यादाओं को बरकरार रखने के लिये जरूरी है कि कघनूनों का इस्तेमाल धार्मिक व जातीय भेदभावध्पक्षपात व द्वेष के बिना हो, ताकि सरकारें सर्वसमाज व सर्वधर्म हितैषी हों और लोगों को लगे भी तथा जिससे सरकारों की संवैधानिक गुडविल प्रभावित ना हो तो यह उचित होगा। बसपा मुखिया ने कहा कि वैसे भी देश के खघसकर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालात इतने कठिन व ज्वलंत समस्याएं इतने अधिक दुखद,कष्टदायी हो गये हैं कि सभी सरकारों को उन विशेष मुद्दों पर अपना ध्यान पूरी तरह से केन्द्रित करना चाहिये, न कि विध्वंसकारी इमेज आदि के माध्यम से लोगों का ध्यान उस पर से बांटने का प्रयास करना चाहिए।

नौ वर्षों में 289 दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में किया ढेर, 34,253 गिरफ्तार

लखनऊ (यूएनएस)। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में नौ वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 289 दुर्दांत अपरधियों को मुठभेड़ में ढेर कर यमलोक पहुंचाया है। पुलिस ने 17,043 मुठभेड़ की कार्रवाइयां कीं, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 11,834 अपराधी घायल हुए। अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गये जबकि 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए।सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज की गईं, जहां पुलिस ने 4,813 कार्रवाई की गईं। इस कार्रवाई में 8,921 अपराधी दबोचे गये जबकि 3,513 अपराधियों को घायल हुए। वहीं 97 कुख्यात अपराधियों को मौके पर ही मार गिराया गया। मेरठ जोन की मुठभेड़ के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दो पुलिसकर्मी शहीद हो गये। एनकाउंटर कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में मेरठ जोन पहले स्थान पर रहा है। वाराणसी जोन में 1,292 मुठभेड़ हुईं, जिनमें 2,426 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया 29 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया।

दोहरा नजरिया ठीक नहीं, मंत्री जयवीर माफी मांगें

उलेमा बोले, इस देश में हिंदू और मुसलमान दो आंखों की तरह

लखनऊ (यूएनएस)। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह के बयान को विवादित बताया है। मौलाना ने कहा कि मंत्री को दोहरे नजरिए से चीजों को नहीं देखना चाहिए। मौलाना अब्बास का कहना है कि मंदिरों में भी सुबह-सुबह घंटियां बजती हैं, उसे भी देखिए, क्योंकि इस देश में हिंदू और मुसलमान दो आंखों की तरह हैं। अगर अजान को लेकर यह कहा जाता है कि उससे नींद में खलल पड़ता है, तो फिर मंदिरों में लाउडस्पीकर पर बजने वाले भजनों को लेकर भी वही बात कही जानी चाहिए। मौलाना ने मंत्री के बयान श्सुबह होने वाली अजान से नींद खराब होती है को आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कहा है। मौलाना ने कहा यह बेहद अफसोस की बात है कि दोहरे नजरिए से देखा जा रहा है। अगर आप मोहब्बत की निगाह से देखिए तो आपको अल्लाह हू अकबर भी अच्छा लगेगा और मंदिरों का भजन भी । मेरे घर

के पास मंदिर है वहां सुबह-सुबह भजन और गीत बजते हैं। हमारे कान को अच्छा लगता है। हमें कोई एतराज नहीं। सुबह-सुबह आवाज आती है 'देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान' इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि इस्लाम धर्म हमें शिक्षा देता है कि हमें किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना है। हम कभी किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं बोलते। यही उम्मीद करते हैं कि इस्लाम धर्म के खिलाफ भी कोई किसी तरह का बयान ना दे। हम लोग मंत्री जयवीर सिंह के इस बयान का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मंत्री इस बयान को वापस ले और मुस्लिम समुदाय से माफी मांगे। मौलाना ने कहा कि अजान इस्लाम धर्म का एक पवित्र हिस्सा है और उसपर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं। हम जो अजान देते है संविधान ने हमें इसकी पूरी आजादी दी है। यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन गुजारें। ठछै के सेक्शन 298,299,302 के तहत हमें आजादी मिली है। कल्चरल मिनिस्टर तत्काल अपने बयान को वापस लें।

एसजीपीजीआई के एलटीयू वार्ड में में मरीज का खून से लथपथ मिला शव

लखनऊ (यूएनएस)। एसजीपीजीआई में भर्ती बजुर्ग मरीज का बेड पर खून से लथपथ शव मिला। धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। पास में खून से सना सर्जिकल ब्लेड भी मिला है। माना जा रहा है कि उसी से मरीज का गला रेता गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड ने साक्ष्य जुटाए हैं। शुरूआती जांच में पुलिस इसे बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करना मान रही है। लेकिन हत्या की बात से भी पूरी तरह से इनकार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल पर बारीकियों से जांच की जा रही है। घटना सोमवार तड़के लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट (एलटीयू) वार्ड में हुई। मृतक की पहचान लिवर कैंसर के मरीज मुस्ताक अली (61) के रूप में हुई। वे बस्ती के रहने वाले थे। वार्ड में ही सो रहे उनके सगे भाई मुख्तार अली को इसकी भनक तक नहीं लगी। मुस्ताक अली के सगे भाई मुख्तार अली उनके साथ वार्ड में थे। वे रात में वार्ड में मुस्ताक अली के पास ही जमीन पर सो रहे थे। मुख्तार का कहना है कि तड़के किसी भी

मुस्ताक अली, मृतक

तरह की चीख-पुकार या आवाज नहीं सुनाई दी। न ही किसी तरह की कोई हलचल हुई। पुलिस के मुताबिक, सुबह पौने छह बजे घटना का आधिकारिक मेमो मिला। जिसके बाद हजरतगंज और स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), अपर उपायुक्त (एडीसीपी)) और सहायक पुलिस आयुक्त (ए) ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। अन्य जगह और कॉरिडोर के कैमरे हैं। उनकी फुटेज खंगाली जा रही है। बस्ती के रहने वाले 61 साल के मुस्ताक अली 21 अप्रैल को लिवर ट्रांसप्लांट विंग में भर्ती थे। गैस्ट्रो विभाग में डॉ. आशीष के अंडर में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें लीवर कैंसर था। एसजीपीजीआई की पीआरओ कुसुम यादव ने बताया कि आज सुबह मुस्तका की मौत की सूचना मिली। एसजीपीजीआई के सीएमएस देवेंद्र गुप्ता ने बताया- सोमवार सुबह पौने छह बजे के करीब मरीज के मौत की जानकारी मिली। ये पहले मेरे भी आईसीयू में भर्ती हुए थे। कैंसर की बीमारी के अलावा आर्थिक तंगी की बात भी सामने आ रही थी। इन्हें हार्ट की भी कुछ समस्या थी। उनका इलाज जरूर चल रहा था पर एडवांस स्टेज कैंसर होने के कारण कंडीशन ठीक नहीं थी। पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है। आगे की डिटेल जांच के बाद ही पता चल सकेगी।

हर पीड़ित को न्याय और पात्र को योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता : केशव

लखनऊ (यूएनएस)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप कार्यालय में 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित, प्रभावी एवं संतोषजनक निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।जनता दर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन एवं युवा उपस्थित रहे। लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी समस्याएं उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। श्री मौर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा पीड़ितों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराएं। 'जनता दर्शन' सरकार और आमजन के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है, वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है और उनका त्वरित समाधान संभव हो पाता है। प्रदेश सरकार जनहित और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है तथा हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी फरियादी निराश नहीं लौटेगा और प्रत्येक समस्या का हरसंभव समाधान किया जाएगा। शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि ऐसा समाधान किया जाए, जिससे पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो तथा उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।भूमि विवाद एवं अवैध कब्जों से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेते हुए श्री मौर्य ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर भेजकर निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ओमप्रकाश राजभर का सपा पर बड़ा हमला, बोले, पीडीए की आड़ में सिर्फ 'यादव' ढूंढना बंद करें अखिलेश

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने सपा के पीडीए को पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने पीडीए की आड़ में सिर्फ यादव ढूंढना बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमलावर है। वे इस मुद्दे पर 20 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका विषय पीडीए ऑडिट, आरक्षण की लूट रखा गया है। अखिलेश यादव ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, भाजपा पीडीए के आरक्षण की लूट का गैंग है। ओमप्रकाश राजभर ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लगता है कि अखिलेश यादव का हाल एकदम ठीक नहीं है। हम उनसे सवाल पूछते हैं और वो साधु संतों को गोली देते हैं। हम

अपनी बात का जवाब देते हैं और वो साधु-संतों को इसमें घसीटते हैं। आप और आपके लोग बात-बात पर साधु-संतों को गाली देना बंद करें। अभी तो कम दुर्गति हुई है, आगे आप लोगों को बड़ा श्राप भोगना पड़ेगा। मंत्री राजभर ने पोस्ट में आगे लिखा, अखिलेश यादव, अब तो आप विपक्ष में हैं, ज्यादातर फ्री ही रहते होंगे। पुराने दिनों को याद कीजिए और 2013 के उस वाले कांड का पर्दाफाश कर दीजिए कि कैसे आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया था, जो हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी था। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये काम आपने 80 से अधिक योग्य उम्मीदवारों के साथ छल करके किया था। मगर, आपकी इस ढीठता भरी नियुक्ति को 14 अक्टूबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अवैध, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 316 का उल्लंघन बता दिया था। राजभर ने कहा, नियुक्तियों में हेराफेरी वाली आपकी सरकार के दौरान बड़े-बड़े कारनामे किए हैं। आपका फॉर्मूला इतना हिट रहा कि 86 में से अकेले 56 यादव एसडीएम बन गए थे? आप लोग क्या-क्या कुचक्र रचते थे। ओमप्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें भी बता दीजिए वो वाला सीक्रेट, जिससे हम राजभर, चौहान, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, प्रजापति, पाल, लोहार, बढ़ई, कहार, धीमर, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, धोबी, सैनी और सभी बहुजन जातियों के लड़के भी एसडीएम बन सकें। अखिलेश आप अपने पीडीए यानी पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश की आड़ में सिर्फ यादव ढूंढना बंद करिए।

ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग-खन्ना

लखनऊ (यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट बैठक में प्रदेश के त्रिस्तरीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसीआरक्षण के निर्धारण के लिए 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को मंजूरी दे दी गई। आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने हेतु उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की समकालीन एवं अनुभवजन्य जांच करेगा। कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और सभी को स्वीकृत कर लिया गया।कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग प्रदेश में पिछड़े वर्गों की स्थिति, उनकी जनसंख्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व और पंचायतों में भागीदारी का समकालीन एवं अनुभवजन्य अध्ययन करेगा तथा निकायवार आनुपातिक आरक्षण निर्धारित करने के लिए अपनी संस्तुतियां देगा।वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल पदों के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यदि जनसंख्या के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तो सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े निर्धारित किए जा सकेंगे। आयोग के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है तथा आयोग का कार्यकाल सामान्य रूप से छह माह का होगा। आयोग प्रदेश की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के उद्देश्य से आंकड़ों का अध्ययन करेगा और निकायवार आनुपातिक आरक्षण की संस्तुति देगा। इसके आधार पर आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी।कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी।

राजधानी में सुबह कई पंपों पर नहीं मिला पेट्रोल,दन चढ़ने के साथ हालात सामान्य

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह कई पंपों पर पेट्रोल नहीं मिला। पंपकर्मियों ने स्टॉक न होने की बात कहकर लोगों को लौटा दिया। इसके बाद अन्य पंपों पर लोगों की भीड़ जुट गई। कोनेश्वर पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों की कतारें लग गईं। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ हालात सामान्य होते दिखे और प्रशासन व पंप संचालकों ने साफ किया कि शहर में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए किसी तरह की अफरा-तफरी की जरूरत नहीं है। आज सुबह लखनऊ के अलग-अलग इलाकों, खासकर पुराने शहर के हिस्सों में कई पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को पेट्रोल नहीं मिल सका। पंप कर्मचारियों ने कुछ समय के लिए स्टॉक खत्म होने की बात कही। लोग बिना पेट्रोल लिए ही वापस लौटे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इससे पहले भी कुछ इलाकों में इस तरह की अस्थायी किल्लत देखी जा चुकी है। खासकर पुराने लखनऊ में सप्लाई और मांग के असंतुलन के कारण समय-समय पर ऐसी स्थिति बन जाती है, जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि दिन बढ़ने के साथ अधिकांश पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य हो गई। लोगों ने रोजमर्रा की तरह पेट्रोल-डीजल भरवाया और कहीं भी लंबी कतारें नहीं दिखीं। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि शहर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कुछ स्थानों पर तकनीकी या सप्लाई में थोड़ी देर की वजह से अस्थायी दिक्कत आई, लेकिन इसे बड़े संकट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रशासन और पंप संचालकों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है। देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव के बाद पंपों पर भीड़ देखी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात शांत हैं। लखनऊ में भी फिलहाल आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बना हुआ है।

69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन

लखनऊ (यूएनएस)। 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों आज, सोमवार को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सड़क पर लेटते हुए मंत्री के आवास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार की नजर में कीड़े-मकौड़े हो चुके हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए आज हम लोग कीड़ों की तरह रेंगते हुए मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। भीषण गर्मी की वजह से कई अभ्यर्थी बदहवास हो गए। पुलिस ने उन्हें पानी पिलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस प्रदर्शन को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का वीडियो पोस्ट करके लिखा। अखिलेश यादव का पोस्ट हूबहू पढ़िए- संविधान द्वारा दिये गये आरक्षण के अधिकार को मारनेवाली भाजपा का अंहकार आज अंदर-ही-अंदर बहुत खुश होगा कि सदियों से वंचित, शोषित, पीड़ित समाज आज भी उनके वर्चस्व के आगे दंडवत होकर याचना कर रहा है लेकिन अपने प्रभुत्व के घमंड में चूर भाजपाई और उनके संगी-साथी ये भी याद रखें कि जब आग्रह हार जाता है, तब इंसान सीमाएं लांघ जाता है। बनारस से आए कैलाश नाथ मौर्या ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से बस यही कहना चाहते हैं कि हम अब अपना धैर्य खो चुके हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं बची है। हम लोग घर से हार चुके हैं और अब सरकार से भी उम्मीद नहीं रही है। यह अंतिम फरियाद है। सुनवाई

नहीं हुई तो हम सभी अभ्यर्थी सामूहिक तौर पर आत्मदाह करेंगे। एक छोटी सी खेती है उसी से घर का खर्च चलता है। हम लोग अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सिस्टम की वजह से बेरोजगार घूम रहे हैं। हाईकोर्ट में जीतने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिली है। हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर कोई हमारे बारे में उल्टा बोलता है। ओम प्रकाश राजभर हमारे मंत्री हैं, जिन्होंने कभी न्याय की बात नहीं की। राजभर कहते हैं कि यह 69000 शिक्षक भर्ती वाले जूता खाने के लायक हैं, यह कितना शर्मनाक बयान है। अगर नौकरी नहीं मिली तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ प्रचार करेंगे और उन्हें चुनाव हरवायेंगे। भीषण गर्मी में रोते गिड़गिड़ाते हुए नवलेश ने बताया कि जौनपुर से आए हैं। हम मुख्यमंत्री और पिछड़ों के मंत्री अनुप्रिया पटेल से कहना चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाइए। हम उन्हीं के बच्चे हैं। पिछले कई सालों से लखनऊ और जौनपुर के चक्कर काट रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो दिल्ली में भी भटकना पड़ रहा है। हम हाथ जोड़कर सरकार से यह कहना चाहते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में हमारी तारीख लगी है। अपना वकील जरूर भेजें। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो जान दे देंगे। इस भर्ती के अभ्यर्थियों में किसी ने अपनी मां खोई है तो किसी ने अपना बाप खोया है। देवरिया से आए धनंजय गुप्ता ने कहा कि हम लोग आज मंत्री संदीप सिंह के आवास पर कीड़ों की तरह रेंगते हुए आए हैं। उनको बताने आए हैं कि आपकी सरकार में पिछड़ा और दलितों की हालत कीड़े-मकौड़े की तरह हो गई है।हम इतना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता पेश हो जाए। 30 से ज्यादा डेट लगी और किसी में भी सरकारी अधिवक्ता करना पहुंचना बेहद शर्मनाक है। फैसला क्या होगा यह तो कोर्ट तय करेगा मगर कम से कम सरकार अपना वकील भेजे और केस आगे बढ़े।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है।राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश के अनुसार प्रदेशभर में ईंधन आपूर्ति की पूरी व्यवस्था सुचारु रूप से काम कर रही है। टर्मिनल, डिपो और पेट्रोल पंपों तक सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के संचालित हो रही है। राज्य में वर्तमान में 13,168 पेट्रोल पंप और 28 सप्लाई डिपो सक्रिय हैं।तेल कंपनियों के अनुसार प्रतिदिन औसतन 20 टीकेएल पेट्रोल और 33 टीकेएल डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। डिपो और रिटेल आउटलेट्स पर इतना स्टॉक मौजूद है कि औसतन 14 दिनों तक की मांग पूरी की जा सकती है। साथ ही रिफाइनरियों से लगातार नए स्टॉक की आपूर्ति भी जारी है।एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। प्रदेश के करीब 4.88 करोड़ उपभोक्ताओं को 4,143 वितरकों और 36 बॉटलिंग प्लांट्स

के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। प्रतिदिन लगभग 8 लाख एलपीजी रिफिल उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही हैं। तेल कंपनियों ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और अस्पताल, रेलवे, रक्षा प्रतिष्ठान, होटल तथा शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए भी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।एलपीजी सेवाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 95 प्रतिशत बुकिंग डिजिटल माध्यमों से हो रही हैं और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) व्यवस्था का पालन भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे डिजिटल माध्यम से ही बुकिंग करें और सुरक्षित वितरण के लिए डिलीवरी के समय डीएसी साझा करें। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की उपलब्धता संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

जौनपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सदर स्थित कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यान, उद्योग, सहकारिता, श्रम, पशुपालन, मत्स्य, खाद्य एवं रसद सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। स्टॉलों पर आमजन को विभागीय योजनाओं, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।बेसिक शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति एवं नामांकन संबंधी जानकारी दी, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन योजनाओं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने ब्रेल लिपि एवं दिव्यांग कल्याण योजनाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण एवं महिला सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी। कृषि एवं

उद्यान विभाग ने किसानों को उन्नत खेती, बीज, उर्वरक एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक किया।उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। सहकारिता विभाग ने किसानों को सहकारी योजनाओं की जानकारी दी, जबकि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। श्रम विभाग ने श्रमिकों को पंजीकरण एवं श्रम कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उद्योग विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत चार आवेदन पंजीकृत किए गए।जिलाधिकारी ने स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए किसानों को पौधे वितरित किए। श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को श्रमिक पंजीयन कार्ड प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में एक हजार से अधिक लोगों ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 81 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 14 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। प्रमोद कुमार निवासी प्रेरमजी, थाना बक्सा द्वारा भूमि विवाद के मामले में विलंब की शिकायत पर जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक को दो दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। वहीं धर्मापुर निवासी राजेश पाल की ओर से न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अवैध निर्माण की शिकायत पर थानाध्यक्ष गौराबादशाहपुर को शाम तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।धर्मापुर शंकरमंडी निवासी श्रीमती इशरत द्वारा बिजली बिल जमा होने के बावजूद एनओसी न मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एक्सईएन हाइडल के प्रति नाराजगी जताते हुए तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा जमीन विवाद, खतौनी एवं विद्युत संबंधी अन्य मामलों पर भी संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।सम्पूर्ण समाधान दिवस के बाद जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को शासन की प्राथमिकताओं, जनसुनवाई, आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारी प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक प्रभावी जनसुनवाई करें और शिकायतों को लंबित न रखें।जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तव पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, सीओ सिटी , उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

मुंगराबादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल

जौनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, श्री कुंवर अनुपम सिंह द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मछलीशहर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार दूबे के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम उ0नि0 धनन्जय राय मय हमराह के मा0 न्यायालर्य एट 6/ इ्रध्णएध 2 जौनपुर द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित एएऊ -295/2020 स्टेट बनाम लहरी व अनुराग मु0अ0सं0-59/20 धारा-354, 323, 504, 506, 376, 511 भादवि व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रिशू उर्फ रितेश कुमार यादव पुत्र जियालाल यादव नविासी ग्राम कैथौली अहमदपुर थाना मुंगराबादशाहपुर जौनपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया। वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-01.रिशू उर्फ रितेश कुमार यादव पुत्र जियालाल यादव निवासी कैथौली अहमदपुर थाना मुंगराबादशाहपुर जौनपुर।गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-01.थानाध्यक्ष श्री अश्वनी कुमार दूबे थाना मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।02.उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।03.का0 दिनेश सोनकर थाना मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

अधिकारी एवं कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचेः डीएम

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में तहसील सदर में कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर प्रेक्षागृह में बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, मत्स्य, उद्यान, वन, उद्योग, सहकारिता, श्रम, स्वरोजगार, खाद्य एवं रसद, कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जहां उन्हें विभागीय योजनाओं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी, उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया, जबकि सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को सहकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा आमजनमानस की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा समस्या के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र अग्रसारित करते हुए गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें तथा साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचे तथा अनुशासन एवं समयबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने जनसुनवाई को अत्यंत गंभीरता से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्त विभागाध्यक्ष प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक प्रभावी रूप से अपने अपने कार्यालयो में जनसुनवाई करें तथा आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

यूजीसी कानून हिंदुओं को लड़ाने वाला, सरकार वापस ले काला कानून : कुंवर हरिवंश सिंह

जौनपुर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने शनिवार को नई कॉलोनी हुसेनाबाद स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूजीसी से जुड़े नए कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज में विभाजन पैदा करने वाला है और हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम करेगा।उन्होंने केंद्र सरकार से इस 'काला कानून' को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार पीछे नहीं हटी तो संगठन कोर्ट से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगा। श्री सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय

महासभा की ओर से इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल स्थगन आदेश (स्टे) दे दिया है।पूर्व सांसद ने बताया कि रविवार को शाम 3 बजे से सिद्धीकपुर स्थित मां दुर्गा जी विद्यालय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन होंगे। साथ ही यूजीसी कानून के विरोध में संगठन की ओर से हुंकार भी भरी जाएगी।इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू, काशी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णन सिंह, प्रदेश महामंत्री राम आश्रय सिंह समेत संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

जौनपुर पुलिस में 12 मुख्य आरक्षी चालक बने सहायक उप निरीक्षक, पीपिंग सेरेमनी में पहनाए गए बैज

क्षेत्राधिकारी ने किया सम्मानित, पुलिस कार्यालय में हुआ आयोजन

मनोज चौबे को बैज पहनाते क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह

जौनपुर। जनपद पुलिस में कार्यरत 12 मुख्य आरक्षी चालकों की सहायक उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति पर पुलिस कार्यालय में पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह ने सभी प्रोन्नत कर्मियों को एसआई के बैज लगाकर सम्मानित किया गया। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा का ही परिणाम है कि आज ये पुलिसकर्मी प्रोन्नत हुए हैं। नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और

ईमानदारी से निभाएं।प्रोन्नत पाने वालों में चालक मनोज चौबे , दिनेश कुमार यादव साधु शरण सिंह, मंगला सिंह, महेन्द्र यादव, राम प्रताप सिंह, बेबी लाल बघेल, योगेन्द्र प्रताप सिंह, विनोद कुमार द्विवेदी, रविशंकर तिवारी, आत्मा सिंह, सत्येन्द्र नाथ पाण्डेय आदि रहे।इस मौके पर पुलिस कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रोन्नति पाने वाले कर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताया और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लिया।

श्रद्धांजलि देने आये अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज

सुजानगंज, जौनपुर। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज द्वारा गौबिष्ट संरक्षण हेतु चलाए जा रहे अभियान यात्रा के अंतर्गत कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सिंह के आवास नागौली नव सुजानगंज पर शुक्रवार देर शाम ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे जहां उन्होंने रात्रि में प्रवास कर शनिवार सुबह पूजन करके पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में भारत सर्वाधिक गोमांस का निर्यात विदेशों में करते हैं इस दौरान उन्होंने इशारे इशारे में कहा की भाजपा सरकार

गोमांस निर्यातकों का तथा गोमांस खाने वालो का संरक्षण भी करती हैं। उन्होंने शुक्रवार को धार भोजशाला मामले मे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर किए। आगे उन्होंने बताया कि यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती और यदि हमें आवश्यकता समझ आती है तो हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जो की जनता में सिर्फ गोवंश संरक्षण के नाम पर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में उन्होंने उपस्थित लोगों को अपनी गोबिष्ट संरक्षण यात्रा में जुड़ने का आह्वान किए। जहां क्षेत्र के भक्त जन उपस्थित रहे।

भू-माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया एवं ट्रांसफर उद्योग के सरगना है पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह- पूर्व मंत्री विजय मिश्र

गाजीपुर। भाजपा के वरिष्?ठ नेता व पूर्व मंत्री विजय मिश्र ने पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह द्वारा जम्?मू कश्?मीर के उप राज्?यपाल पर की गयी टिप्?पणी को निंदनीय बताया।उन्होने कहा कि यह टिप्?पणी पूर्व मंत्री की घटिया सोच, उनकी हताशा और निराश को दर्शाता है। उन्?होने बताया कि पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह के लंबे राजनीतिक जीवन के उपलब्?धि? के बारे में गाजीपुर की जनता कहती है कि वह भू-माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया एवं ट्रांसफर उद्योग के सरगना हैं। बिजली, सिंचाई और पीडब्?ल्?यूडी विभाग के इंजीनियरों, बीएसए, डीआईओएस, और बीडीओ के ट्रांसफर, पोस्टिंग का सेटिंग एवं अधिकारियों को डरा-धमकाकर व मारपीट कर भ्रष्?टाचार करते हैं। कई बार अवसर प्राप्?त होने के बाद भी गाजीपुर की जनता की एक भी जरुरत पूरा नही किया और भाजपा का देश में बढ़ते हुए जनाधार से अब उन्?हे एहसास हो गया है कि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। बढ़ते हुए उम्र में गिल्?टी फील कर रहे हैं। डिप्रेशन में आकर गाली-गलौज कर रहे हैं। उन्?होने कहा कि मनोज सिन्?हा गाजीपुर के गौरव हैं। उनके कार्य और स्?वभाव से गाजीपुर को देश-विदेश में एक नया सम्?मान मिला है। मनोज सिन्?हा ने बनारस- गाजीपुर-गोरखपुर फोरलेन, मेडिकल कालेज, पूर्वांचल एक्?सप्रेस-वे, ग्रीन फील्?ड एक्?सप्रेस-वे, गंगा नदी पर रेलवे ब्रिज, औड़िहार में मेमो सेड ट्रेनिंग सेंटर और गाजीपुर में रेलवे ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कराया। उन्?होने कहा कि मैने अपने कार्यकाल में जिला अस्?पताल, सौ बेड का महिला अस्?पताल, ट्रामा सेंटर, स्?टेडियम, ऑडिटोरियम, बिजली व्?यवस्था को सुसारु बनाने के लिए ट्राली ट्रांसफार्मर, सड़क, पुल, आदि का निर्माण कराया। पूर्व मंत्री विजय मिश्र ने बताया कि ओमप्रकाश सिंह सात बार विधायक, दो बार मंत्री, और एक बार सांसद रहे हैं। गाजीपुर के किसी भी जरुरत को पूरा करने के लिए कोई भी कार्य कराये हैं तो वह बताएं? उन्?होने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बाद सपा विचारशून्?य और विवेकहीन पार्टी हो गयी है। सपा नेताओं में सनातन और हिंदु समाज को अपशब्?द और अपमानित करने और पीएम मोदी व भाजपा को गाली देने की प्रतियोगिता चल रही है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, भानुप्रताप पुत्र डॉ. उदयराज यादव एवं माता श्रीमती मन्नो देवी, निवासी ग्राम बेल्छा, पोस्ट मसीदा, थाना बक्शा, जिला जौनपुर, पिनकोड 222132,यह घोषणा करता हूँ कि पहले मेरा नाम 'भानुप्रताप' था।

मोबाइल नंबर 7800348309

अब से मैं अपना नाम 'भानुप्रताप यादव' रखता हूँ तथा भविष्य में सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं सामाजिक कार्यों में मैं 'भानुप्रताप यादव' नाम से जाना जाऊँगा।

इटली और भारतः इंडो-भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक साझेदारी

नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी, इटली गणराज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष

भारत और इटली के संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। यह संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। यह संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहा है, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है।हमारा सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा तथा विविध बनाने का संकल्प लिया है, ताकि नए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। हम इटली की डिजाइन क्षमता, बेहतरीन विनिर्माण कौशल और विश्वस्तरीय सुपरकंप्यूटर तकनीक–जो उसे एक औद्योगिक महाशक्ति बनाती है–को भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, बड़े पैमाने की क्षमता, नवाचार और 100 से अधिक यूनिकॉर्न तथा 2 लाख स्टार्ट-अप वाले उद्यमी इकोसिस्टम के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं। यह केवल दो व्यवस्थाओं का

साधारण मेल नहीं है, बल्कि ऐसा साझा मूल्य निर्माण है जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक ताकतें एक-दूसरे को और अधिक मजबूत बनाती हैं।यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पुर्जे, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि-खाद्य क्षेत्र और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। 'मेड इन इटली' हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है, और आज इसका स्वाभाविक तालमेल 'मेक इन इंडियापहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ दिखाई देता है। इसी संदर्भ में, भारत के लिए उत्पादन में इतालवी कंपनियों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी – जो अब दोनों पक्षों से मिलाकर 1000 से अधिक हो चुकी है – एक

सकारात्मक संकेत है। यह हमारी सप्लाई चेन के एकीकरण को और मजबूत करेगी।तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया एक बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। भारत का तेज़ी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या, तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता– इन क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती है। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच बढ़ती साझेदारी भी इसे मजबूती देगी।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों, के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इटली और भारत लंबे समय से इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं, ताकि एआई का विकास जिम्मेदार और मानव-केंद्रित हो।भारत और इटली एआई को समावेशी विकास का एक शक्तिशाली माध्यम भी मानते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान, बहुभाषी तकनीकों के जरिए एआई सामाजिक और डिजिटल खाइयों को कम कर सकता है, न कि उन्हें और बढ़ा सकता भारत के मानव विज़न- यानी तकनीक के केंद्र में मानव को रखने की सोच और इटली की मानव-केंद्रित 'एल्गोर-एथिक्स'की अवधारणा, जो उसकी मानवतावादी परंपरा पर आधारित है, पर आगे बढ़ते हुए हमारी साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बने।हमारा दृष्टिकोण भारत की विशाल डिजिटल क्षमता को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, ताकि तकनीक मानव गरिमा की सेवा कर सके।

सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करके, हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश एआई का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। यही सोच इटली की जी7 अध्यक्षता और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के निष्कर्षों का मुख्य आधार है। एआई को इंसानों की ओर से इंसानों के लिए बनाई गई तकनीक मानने का अर्थ है यह स्पष्ट करना कि तकनीक न तो मनुष्य की जगह ले सकती है और न ही उसके मूल अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसका उपयोग जनमत को प्रभावित करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए भी नहीं होना चाहिए।आज की तेजी से जुड़ी हुई दुनिया में स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा का हमारा दृष्टिकोण इसी चुनौती पर आधारित है।हमारा सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान और सैटेलाइट तकनीक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति तथा इटली की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, संयुक्त परियोजनाओं और नई पीढ़ी की तकनीकों के विकास के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और स्थिरता बेहद आवश्यक हैं। इसलिए इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीकों जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सहयोग महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी चुनौतियों के खिलाफ मजबूती बढ़ाने में मदद करेगा। ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण आधार है। दुनिया में ऊर्जा के विविध स्रोतों की ओर बढ़ रहे बदलाव के लिए नवाचार, निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। भारत और इटली नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन तकनीक, तथा स्मार्ट ग्रिड से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की पहल अपार संभावनाएं रखती है। यह इटली की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में उन्नत तकनीक और यूरोप के लिए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में उसकी रणनीतिक भूमिका के साथ पूरी तरह मेल खाती है।इस संदर्भ में भारत की अगुवाई वाली प्रमुख पहलों- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) में अन्य देशों के साथ हमारा सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण है। भौतिक, डिजिटल और मानवीय संपर्क ही वह कड़ी है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। भारत और इटली दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों-इंडो-पैसिफिक और भूमध्यसागर के केंद्र में स्थित हैं। अब इन क्षेत्रों को अलग-अलग नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, हम एक नए 'इंडो-मैडिटेरेनियन' क्षेत्र के उभरने को देख रहे हैं, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक महत्वपूर्ण गलियारा बन रहा है और हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है।इसी आपस में जुड़े हुए क्षेत्र में हमारा संबंध स्वाभाविक रूप से एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित होता है- ऐसी साझेदारी, जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है और नई वैश्विक परिस्थितियों को आकार देती है।इस संदर्भ में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) एक ऐसी दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों और मजबूत सप्लाई चेन के माध्यम से हमारे क्षेत्रों को जोड़ना है। भारत और इटली अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।हम अपने साझा चुनौतियों का समाधान दोनों देशों के गहरे संबंधों और लंबे सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में 'धर्म' का विचार उस जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वहीं 'वसुधैव कुटुंबकम्'- अर्थात 'पूरी दुनिया एक परिवार है' का सिद्धांत आज के आपस में जुड़े डिजिटल युग में और भी अधिक प्रासंगिक लगता है।ये मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा से भी मेल खाते हैं, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण काल में हैं। यह परंपरा हर व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति की उस शक्ति पर जोर देती है, जो समाजों और लोगों को एकजुट कर सकती है। इसलिए हमारी साझा दृष्टि का उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखते हुए भारत-इटली साझेदारी को मजबूत, आधुनिक और भविष्य उन्मुख आधार प्रदान करना है।

स्वदेश भारत न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक स्वदीश कुमार द्वारा स्वदेश भारत पब्लिकेशन ग्राम कनकपुर पोस्ट फतेहगंज जिला जौनपुर (उ0प्र0) 222132 से मुद्रित एंव प्रकाशित ।
सम्पादक
स्वदीश कुमार
मो0 9628825379
संरक्षक संजय गुप्ता
7860079888
उप संरक्षक- आदित्य मौर्या
प्रधान संम्पादक- राकेश मौर्या
उप संम्पादक – नियामअतुल्ला
समाचार संम्पादक- विनय कुमार
सह संपादक- तबरेज नियाजी
कार्यकारी सम्पादक
राजेश गौतम, सतीश चौहान
प्रबन्ध संम्पादक –रंजीत कुमार
@-swadeshbharatnews@gmail-com

समस्त वादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा